नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 063
दि. 02.07.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'सहारनपुर में पहले दंगे होते थे, अब विकास हो रहा', सीएम योगी ने याद दिलाया सपा सरकार का दौर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने राज्यव्यापी 'स्कूल चलो अभियान' के दूसरे चरण की शुरूआत भी की।

(जीएनएस)।

सहारनपुरः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां 613 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने याद दिलाया कि यूपी में पूर्व में जब सपा की सरकार थी तो सहारनपुर में दंगे होते रहते थे। उन्होंने कहा कि अब सहारपुर का तेजी से विकास हो रहा है।

दंगा, कर्फ्यू हमारी नियति बन चुके थे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या यह 2017 के पहले संभव था, नहीं। 2017 के पहले सहारनपुर में दंगे होते थे। मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे। मेरठ, अलीगढ़, मथुरा में दंगे होते थे। दंगा, कर्फ्यू हमारी नियति बन चुके थे। कैराना, कांधला से पलायन होता था। ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे। न बेटी सुरक्षित थी,न व्यापारी सुरक्षित था,कानून व्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। याद करिए 2011-12 में मुरादाबाद में डीआईजी पर हमला हो जाता है,उपद्रवी मरा हुआ समझकर छोड़कर गए थे।

सपा ने उपद्रवियों पर मुकदमा नहीं चलाया

ॅउन्होंने कहा कि, समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया, उनके केस वापस लेने का प्रयास कर रही थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे। पिछले दिनों हमने उन्हें सजा भी करवा दी है। अब सहारनपुर में दंगा नहीं होता। अब सहारनपुर में मां शाकुम्भरी के भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है।

मुख्यमंत्री योगी ने कही कि, जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। समाजवादी पार्टी तो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए महापुरुषों की जन्मजात विरोधी रही है।

तेज विकास से अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत होगी

सीएम योगी ने कहा कि, सहारानपुर का व्यक्ति सहारनपुर से दिल्ली के लिए चलता है तो उसे पता

ही नहीं लगता, वह डेढ़ घंटे में दिल्ली पहुंच जाता है। विकास की रफ्तार इन्फ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, यह अर्थव्यवस्था को भी उड़ान दे रही है। जितनी अच्छी सड़कें होंगी, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी उतनी है विकास की रफ्तार तेज होगी। विकास की रफ्तार जितनी तेज होगी, अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होकर आगे बढ़ेगी। यही तो 2017 के बाद हुआ। दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया। अब सहारनपुर एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। सहारनपुर के पास अपना एयरपोर्ट होगा।

एक्सपोर्ट हमारी वास्तविक ताकत

मुख्यमंत्री ने कहा कि, सहारनपुर के हस्त शिल्पियों ने विपरीत परिस्थितियों में भी वुड कार्विंग की अपनी परंपरा को जीवित रखा। आज वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट के माध्यम से वह सहारनपुर को वैश्विक पहचान दे रहा है। एक्सपोर्ट की ताकत हमारी वास्तविक ताकत है। जिस देश के पास एक्सपोर्ट की जितनी ताकत होगी, वह उतना ही धनी होगा। विदेशी मुद्रा को अपने देश में लाने का सामर्थ्य विकसित करेगा।

कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरूआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, क्योंकि यह केवल परिवार की नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की भी क्षति है। उन्होंने सहारनपुर के जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, शिक्षकों, सांसदों, विधायकों और समाज के सभी वर्गों से अपील की कि 'स्कूल चलो अभियान' को एक जनआंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जाए।

मुख्यमंत्री योगी ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा ही अच्छे नागरिक, शिक्षक, चिकित्सक, अधिकारी और जनप्रतिनिधि तैयार करती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की प्रगति का आधार शिक्षा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न केवल बच्चों को संस्कारित और आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि उन्हें समाज और देश के विकास में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए भी तैयार करती है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू किए गए 'स्कूल चलो अभियान' का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना था और इसके सकारात्मक परिणाम आज पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं।

जापान के लिए भारत क्यों है अहम?: पीएम ताकाइची ने दिल्ली रवाना होने से पहले बताई वजह, कल पीएम मोदी से मुलाकात

(जीएनएस)।

टोक्यो ,जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची बुधवार को भारत दौरे पर रवाना हो गईं। भारत दौरे से पहले उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा और निवेश-नवाचार जैसे मुद्दों पर ठोस सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी।

जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने बुधवार को भारत दौरे से पहले आयोजित एक अनौपचारिक प्रेस वार्ता में कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच भारत के साथ सहयोग का महत्व और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के साझा मूल्यों तथा रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के बीच सहयोग को नई दिशा देने का यह महत्वपूर्ण अवसर है। ताकाइची बुधवार शाम भारत पहुंचेंगी और गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी।

भारत के साथ सहयोग का महत्व लगातार बढ़ रहा है-ताकाइची

प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता के बीच भारत के साथ सहयोग का महत्व लगातार बढ़ रहा है। इस यात्रा के दौरान मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तीन प्रमुख क्षेत्रों पर ठोस सहयोग को आगे बढ़ाना चाहती हूं। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में जापान-भारत रणनीतिक सहयोग संबंधों को और गहरा करना, आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना तथा दोनों देशों की कंपनियों के बीच निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करना शामिल है।

जापानी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत यात्रा के दौरान जापान-भारत आर्थिक मंच का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें जापान के कारोबारी समुदाय से 150 से अधिक लोग भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार और निजी क्षेत्र को साथ लाकर दोनों देशों के सहयोग का दायरा बढ़ाने और मजबूत अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

भारत क्यों जापान के लिए जरूरी?

ताकाइची ने कहा कि भारत, जापान की तरह एशिया का एक प्रमुख लोकतांत्रिक देश है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ 'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक' (एफओआईपी) की दिशा में प्रयासों पर भी चर्चा होगी। इस दौरान जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के ढांचे से जुड़े सहयोग पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर हो रही है और वह इसे उनके साथ व्यक्तिगत विश्वास के संबंधों को और मजबूत करने का अवसर मानती हैं। इससे पहले बुधवार को सानाए ताकाइची 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए टोक्यो से भारत के लिए रवाना हुईं।

उपराष्ट्रपति ने आईसीएआई के 78वें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस समारोह को संबोधित किया

भारत के उपराष्ट्रपति, श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स "भरोसे के दूत" हैं और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में उनका विशेष महत्व है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के 78वें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस एवं स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक सुशासन सुनिश्चित करता यह पेशा भारत के आर्थिक एवं संस्थागत विकास का केंद्र है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी को अब 15 जुलाई तक देनी होगी अंतिम रिपोर्ट, सीएम योगी ने दिया अतिरिक्त समय

(जीएनएस)।

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़े दान प्रकरण की जांच अभी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) को अतिरिक्त समय देते हुए उसकी रिपोर्ट सौंपने की नई समय-सीमा 15 जुलाई तय कर दी है।

एसआईटी ने जांच के दौरान सामने आए विभिन्न तथ्यों और साक्ष्यों की गहन पड़ताल के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी।

किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले की जांच पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ होगी। उन्होंने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध

पर ही इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था।

गौरतलब है कि 23 जून को एसआईटी के प्रमुख सदस्य और लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी। रिपोर्ट में कई अहम बिंदुओं पर कार्रवाई की संस्तुति किए जाने की जानकारी सामने आई थी। इसी प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को श्रीराम जन्मभूमि थाने में पहली एफआईआर दर्ज की गई।

आठ लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया

ट्रस्ट सदस्य कृष्णमोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज इस मुकदमे में आठ लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया, जबकि कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों को भी आरोपी के रूप में शामिल किया गया है। पुलिस सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब एसआईटी मामले के शेष पहलुओं की गहन जांच में जुटी हुई है। 15 जुलाई तक जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की दिशा तय होने की संभावना है।

सहारनपुर से सीएम योगी ने किया 'स्कूल चलो अभियान' के दूसरे चरण का शुभारंभ, बोले- कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न हे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से राज्यव्यापी 'स्कूल चलो अभियान-2026' के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को स्कूल पहुंचाना समाज और राष्ट्र की जिम्मेदारी है।

(जीएनएस)।

सहारनपुरः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सहारनपुर से राज्यव्यापी 'स्कूल चलो अभियान-2026' के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज का राष्ट्रीय दायित्व है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को नई शैक्षणिक सत्र की पाठ्य-पुस्तकें, स्कूल बैग और स्टेशनरी वितरित की तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रधानाध्यापकों को सम्मानित भी किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिशक्ति मां शाकुंभरी देवी की कृपा

भूमि सहारनपुर से शुरू हो रहा यह अभियान प्रदेश के हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए सम्मानित शिक्षकों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विमान सरसावा एयरपोर्ट पर उतरा, जहां से वे सीधे जनता रोड स्थित महाराज सिंह डिग्री कॉलेज मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ करने के साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।

बारिश के बावजूद उमड़ी भीड़

सुबह से हो रही बारिश के बावजूद कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए थे।

'शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत'

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा ही भविष्य के अच्छे शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, उद्यमी और जनप्रतिनिधि तैयार करती है।

'पीएम मोदी के पास सुनहरा मौका, आरएसएस भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भारत-पाकिस्तान के बीच बातचीत बहाल करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास जम्मू-कश्मीर मुद्दे के समाधान का सुनहरा अवसर है.

(जीएनएस)।

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि दत्तात्रेय होसबोले और मोहन भागवत समेत फर के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी पाकिस्तान के साथ बातचीत की जरूरत बताई है. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इस समय एक सुनहरा अवसर है. उनके अनुसार, अगर भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपस में बातचीत शुरू करें तो कई पुराने मुद्दों का समाधान निकल सकता है.

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का मुद्दा लंबे समय से दोनों देशों के बीच तनाव की बड़ी वजह बना हुआ है. अगर बातचीत का रास्ता खुलता है तो इस समस्या के समाधान की दिशा में भी आगे बढ़ा जा सकता है. महबूबा मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए और दोनों देशों के बीच बंद पड़े बॉर्डर भी खुलने चाहिए. उनका मानना है कि लोगों के बीच संपर्क बढ़ने और बातचीत से रिश्तों में सुधार आ सकता है.

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच लोगों का आना-जाना, बातचीत और विचारों का आदान-प्रदान होना चाहिए. उनके मुताबिक, अच्छे पड़ोसी संबंध क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए बेहद जरूरी हैं.

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि वाजपेयी जी ने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज यह बात फिर से सही साबित होती दिख रही है.

लखनऊः प्रो. शेरी बने आईआईएम शिलांग के निदेशक, ट्रिपलआईटी लखनऊ के हैं संस्थापक निदेशक

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी (ट्रिपलआईटी) लखनऊ के निदेशक प्रो. अरुण मोहन शेरी को शिक्षा मंत्रालय ने आईआईएम शिलांग का नया निदेशक नियुक्त किया है। वे पांच साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। प्रो. शेरी फरवरी 2019 में ट्रिपलआईटी लखनऊ के निदेशक बनाए गए थे। प्रो. शेरी इससे पहले आईआईएमटी गाजियाबाद, नरसी मोंजी मुंबई, एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों व प्रतिष्ठानों में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने उन पर जो भरोसा जताया है, वह उसे बेहतर तरीके से पूरा करने का प्रयास करेंगे।

राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुई

भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु आज 1 जुलाई, 2026 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुरमु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह न केवल उत्सव मनाने का दिन है, बल्कि इस नए संस्थान की विकास-यात्रा का एक निर्णायक चरण भी है। उन्होंने कहा, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भविष्य के लिए पूर्णतः तैयार संस्थान बनने के लिए यह विश्वविद्यालय एक दूरगामी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों और विशेषकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता, समावेशी और समतामूलक विकास के प्रति उत्तरदायित्व की भावना दशार्ती है।

अखिलेश यादव का जन्मदिन , सीएम योगी और बसपा प्रमुख मायावती समेत कई नेताओं ने दी बधाई

(जीएनएस)।

नई दिल्ली/लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उन्हें सियासी गलियारों से लगातार बधाइयां और शुभकामनाएं मिल रही हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने सपा प्रमुख को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीघार्यु की कामना की है।

सीएम योगी ने लिखा, 'उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके लिए आरोग्यता और दीघार्यु की प्रार्थना है।'

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके

लिए आरोग्यता और दीघार्यु की प्रार्थना है।

बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा, 'समाजवादी पार्टी के प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान में सपा सांसद श्री अखिलेश यादव जी को आज उनके जन्मदिन पर उन्हें व उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई एवं उनके अच्छे जीवन व लम्बी उम्र की शुभकामनायें।'

समाजवादी पार्टी के प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान में सपा सांसद श्री अखिलेश यादव जी को आज उनके जन्मदिन पर उन्हें व उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई एवं उनके अच्छे जीवन व लम्बी उम्र की शुभकामनायें।

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा प्रमुख को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मयार्दा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण और आदि देव महादेव की कृपा अखिलेश यादव पर बरसे और आप सदैव स्वस्थ रहें और दीघार्यु हों।'

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

आखिर 1600 सीसीटीवी कैमरों की नजर से कैसे बच गई अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी?

राम मंदिर में सुरक्षा और निगरानी के लिए कम से कम 1600 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके अलावा मंदिर प्रांगण के बाहर भी हजारों कैमरे लगे हैं। लेकिन 'जब ऊपर वाला सब देख रहा था', फिर भी करोड़ों रुपए कैसे चोरी हो गए? यह अभी तक रहस्य ही है।

(जीएनएस)।

अयोध्या राम मंदिर में 'चंदा चोरी' का रहस्य सुलझने के बजाए गहराता जा रहा है। मामले की जांच के लिए एसआईटी (विशेष जांच दल) बना, एफआईआर हुई, कुछ लोग गिरफ्तार हुए और राम मंदिर ट्रस्ट के कुछेक पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन कुछ सवाल अनुत्तरित हैं, जिन पर न तो ट्रस्ट, न संघ, न बीजेपी और न ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कुछ बोल रही है।

सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बीजेपी की चुनावी राजनीति का मुख्य मुद्दा बना अयोध्या में राम मंदिर क्या इतनी कमजोर सुरक्षा व्यवस्था से प्रबंधित हो रहा था या है कि वहां से करोड़ो रुपए (पूरा आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है) का चंदा चोरी हो गया। देश के करोड़ों नागरिकों की तमाम तरीकों से निगरानी करने वाली सरकार क्या चंदे की निगरानी की व्यवस्था करने में नाकाम रही। मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर प्रांगण में जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उनमें पल-पल की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग होती है। राजनीति

अयोध्या राम मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए 10,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से करीब 800 से 1,600 कैमरे सीधे मंदिर परिसर, दान पेटी और गर्भगृह की निगरानी के लिए हैं। इसके अलावा मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं।

सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए इनमें से कई कैमरों में एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।

मंदिर परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए आधुनिक कैमरे 24७7 सक्रिय रहते हैं।

इन सभी कैमरों की लाइव फीड पुलिस और सुरक्षा बलों के विशेष कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड की जाती है।

अऋएफळकरएटएठळ

मंदिर में दान-पात्रों और चढ़ावे की गिनती वाले कमरों में विशेष हाई-डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे।

यह तो रही जानकारी पूरे मंदिर परिसर में लगे कैमरों की। लेकिन फोकस में दान पात्र और वह कक्ष है जहां चढ़ावे में आए चंदे की गिनती आदि होती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे मंदिर परिसर में अलग-अलग जगहों पर 40 दान पात्र रखे गए हैं। इन्हीं दान पात्रों में श्रद्धालु अपनी हैसियत मुताबिक नकद रकम, नोट, सिक्के, सोने-चांदी के गहने आदि डालते हैं। इन दानपात्रों को मंदिर उद्घाटन के शुरूआती दिनों में दिन कम से कम दो बार खोला जाता था क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर आ रहे थे और दान पात्रों में चंदा डाल रहे थे। फिलहाल कितनी बार दानपात्रों को खोला जाता है इसकी अधिकारिक जानकारी नहीं है।

दानपात्र खोलने की एक प्रक्रिया तय की गई थी। इसके तहत दान पात्र खोलते समय मंदिर ट्रंस्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी, इस काम के लिए विशेष रुप से नियुक्त कर्मचारी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी या कर्मचारी की मौजूदगी में खोला जाता है। इन पात्रों में मिले पैसे-गहनों आदि को लोहे को कंटेनर में तालाबंद कर गणना कक्ष में ले जाया जाता है।

दान गणना कक्ष (काउंटिंग रूम) मंदिर परिसर के अंदर, मुख्य मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर यात्री सुविधा केंद्र के बेसमेंट में स्थित है।यह स्थल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रशासनिक नियंत्रण और सुरक्षा घेरे के अंतर्गत आता है।

अऋएफळकरएटएठळ

गणना कक्ष में सभी 40 दानपात्रों से मिला धन लाया जाता है। इस गणना कक्ष में 44 लोगों की दो शिफ्ट में ड्यूटी लगती है। इनमें एक इंचार्ज होता है, एक सुपरवाइजर और 4-5 टेलर यानी रोकड़िया है जो पैसे का लेन-देन करता है। इस टीम में ट्रस्ट के अधिकारी, बैंक के अधिकारी कुछ स्थानीय वॉलंटियर होते हैं जिन्हें ट्रस्ट ने नियुक्त किया होता है। गिनती करने वाले लोगों के लिए बिना जेब के कपड़े पहनने का नियम बनाया गया था जिसपर स्टेट बैंक और ट्रस्ट दोनों सहमत हुए थे। लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया।

दानपात्रों की लोकेशन, उससे मिले धन को गणना केंद्र तक लाने वाले रास्ते और गणना कक्ष, सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है। रिपोर्ट में सामने आया है कि सभी कैमरों की स्टोरेज क्षमता सिर्फ 45 दिन की रिकॉर्डिंग रखने की ही है और उसके बाद सारी फुटेज वह ऑटो डिलीट हो जाती है। यह ऐसा पेंच है जिसका जवाब फिलहाल नहीं मिला है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि एसआईटी डिलीट हुए फुटेज को रिकवर करने की कोशिश कर रही है।

गणना कक्ष में लगे सीसीटीवी की जो भी रिकॉर्डिंग मिली है, उसमें कुछ चौंकाने वाले पहलू सामने आए हैं। रिकॉर्डिंग से पता चला है कि गिनती के दौरान नोटों के बंडल तय की गई ट्रे या बैंक के कंटेनर में न रखकर कुछ खास व्यक्तियों के हाथों में दिए जा रहे हैं। यह खास व्यक्ति कौन हैं, इसका खुलासा होना बाकी है।

एक और अहम खामी गणना कक्ष में सामने आई है। जानकारी के मुताबिक गिनती में लगे कुछ कर्मचारी खासतौर से गणना कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन के सामने इस तरह बैठते हैं जिससे पूरे कमरे और पूरी प्रक्रिया सामने आ ही नहीं पाती है। यानी कैमरे के लेंस में उनकी पीठ ही नजर आ पाती है।

लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मंदिर परिसर में लगे हर कैमरे की लाइव मॉनिटरिंग की जाती है। इसके लिए बाकायदा कंट्रोल रूम भी बना हुआ है। तो फिर कैमरों के सामने आ रहे ऐसे व्यवधान को नोट क्यों नहीं किया गया और इसकी जानकारी ट्रस्ट को कैसे नहीं हुई?

अऋएफळकरएटएठळ

यहां एक व्यक्ति का नाम सामने आता है। अर्जुन देव...यह सरकारी कर्मचारी हैं और अयोध्या में बीते 17 साल से रेडियो मेंटेनेंस अधिकारी के तौर पर तैनात थे। मंदिर परिसर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करना इनकी ही जिम्मेदारी थी। लोगों का कहना है कि यह ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय (जो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन इस्तीफे की मंजूरी अभी बाकी है) के नजदीकी थे। एसआईटी की जांच के दौरान इनका नाम सामने आया है। लेकिन इससे पहले ही इनका तबादला गोरखपुर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक इनसे पूछताछ नहीं हुई है। कहा जाता है कि पूर्व में भी इनके तबादले के आदेश होते रहे लेकिन हर बार किसी न किसी की सिफारिश से इनका तबादला रोक दिया गया था।

इन सारी बातों और जानकारियों के सामने आने के बाद अब साफ होता जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरों की निगरानी महज एक खानापूरी थी, और उनकी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पूरे परिसर में ऐसे कई ब्लाइंड स्पॉट भी मौजूद हैं जहां सीसीटीवी कैमरे की नजर नहीं पहुंच पाती।

चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने सीए को बधाई दी

(जीएनएस)।

नई दिल्ली, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने सीए को बधाई दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के अवसर पर सीए को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बधाई देते हुए लिखा, 'पूरे सीए समुदाय को 'चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे' की बधाई। वे लंबे समय से भारत की आर्थिक यात्रा में भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं। पारदर्शिता और पेशेवर उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से, वे हमारे वित्तीय सिस्टम को मजबूत करते हैं, व्यवसायों को सहारा देते हैं, उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं और निवेशकों का भरोसा बढ़ाते हैं।'

प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट पर आगे लिखा, 'उनकी विशेषज्ञता आर्थिक विकास और राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे-जैसे हम 'विकसित भारत' बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी कोशिशें ऐसा माहौल बनाने में मदद करती हैं जहां उद्यम फल-फूल सकें और सभी के लिए अवसर बढ़ सकें।'

गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई देते हुए 'एक्स' पोस्ट पर लिखा, 'चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे पर सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं। वे व्यक्तियों और व्यावसायिक घरानों की वित्तीय दक्षता और कानूनी अनुपालन को लगातार बेहतर बनाकर हमारे देश की आर्थिक प्रगति में

योगदान देते हैं। यह दिन देश के प्रति उनके समर्पण को और मजबूत करे।'

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, 'वित्तीय ईमानदारी और आर्थिक प्रगति के आधार-स्तंभों को 'चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे' की हार्दिक शुभकामनाएं। नैतिकता, सटीकता और पारदर्शिता के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से, आप व्यवसायों को मजबूत बनाने, विश्वास को बढ़ावा देने और भारत की प्रगति व समृद्धि में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी सीए पेशेवरों को उनके इस नेक पेशे में निरंतर सफलता और उत्कृष्टता की शुभकामनाएं।'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, 'सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट साथियों को 'चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस' की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी विशेषज्ञता, निष्ठा और व्यावसायिक उत्कृष्टता देश की आर्थिक प्रगति को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने में आपका योगदान अत्यंत अभिनंदनीय है।'

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, 'सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को 'चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस' की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी विशेषज्ञता, ईमानदारी और उत्तरदायित्व राष्ट्र की आर्थिक प्रगति की मजबूत नींव है।'

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बधाई देते हुए 'एक्स' पोस्ट में लिखा, 'राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस पर चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय को बधाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट भारत की विकास यात्रा में भरोसेमंद साझेदार हैं। स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने और एमएसएमई को मजबूत करने से लेकर पारदर्शिता, नियमों के पालन और वित्तीय अनुशासन के साथ उद्यमों को सहयोग देने तक, आपका योगदान एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने में मदद कर रहा है। देश के प्रति समर्पित सेवा के लिए हर सीए को शुभकामनाएं।

लखनऊ मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के सात अंडरग्राउंड स्टेशनों का निर्माण शीघ्र, सबसे बड़ा सिविल टेंडर जारी

लखनऊ मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के पूरा होने पर चारबाग से वसंतकुंज तक तेज, सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा। .. चारबाग से वसंतकुंज तक प्रस्तावित 11.165 किलोमीटर लंबा ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर ₹1877.89 करोड़ की अनुमानित लागत से चारबाग से चौक तक बनेगा अंडरग्राउंड मेट्रो सेक्शन

(जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) ने लखनऊ मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (फेज-1बी) के निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

चारबाग से वसंतकुंज तक प्रस्तावित 11.165 किलोमीटर लंबे ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के अंतर्गत बनने वाले 7 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों एवं संबंधित सुरंग निर्माण के लिए लगभग ₹1877.89 करोड़ का प्रमुख सिविल निर्माण टेंडर जारी कर दिया गया है। यह परियोजना लखनऊ मेट्रो फेज-1बी का अब तक का सबसे बड़ा सिविल टेंडर है।

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जानकारी दी है कि यूपीएमआरसी लगभग ₹5801 करोड़ की लागत से लखनऊ मेट्रो फेज-1बी (ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर) का निर्माण कर रहा है। परियोजना के तहत पांच

एलिवेटेड एवं सात अंडरग्राउंड सहित कुल 12 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। एलिवेटेड व अंडरग्राउंड दोनों सेक्शन का निर्माण समानांतर रूप से किया जाएगा, जिससे निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे कॉरिडोर पर मेट्रो संचालन शुरू किया जा सके।

28 जुलाई को खोला जाएगा टेंडर

टेंडर प्रक्रिया के अनुसार, 28 जुलाई 2026 को टेंडर खोला जाएगा। सफल बोलीदाता के चयन के बाद कार्यादेश जारी किया जाएगा तथा कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 36 माह के भीतर निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। इस टेंडर के अंतर्गत चारबाग से चौक तक अंडरग्राउंड मेट्रो सेक्शन का निर्माण किया जाएगा। इसमें आधुनिक सुरंग निर्माण के साथ सात अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों का निर्माण भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, चौक मेट्रो स्टेशन से एलिवेटेड कॉरिडोर को जोड़ने के लिए लगभग 350 मीटर लंबा रैंप भी निर्मित किया जाएगा।

यूपीएमआरसी ने ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के एलिवेटेड सेक्शन के लिए पांच मेट्रो स्टेशनों, वायाडक्ट तथा वसंतकुंज मेट्रो डिपो के निर्माण से संबंधित टेंडर पहले ही जारी कर दिया है। अब अंडरग्राउंड सेक्शन का टेंडर जारी होने के साथ परियोजना के सभी प्रमुख सिविल पैकेजों की निविदा प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है।

ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (फेज-1बी) में सात अंडरग्राउंड स्टेशन

चारबाग मेट्रो स्टेशन, गौतमबुद्ध मार्ग मेट्रो स्टेशन, अमीनाबाद मेट्रो स्टेशन, पांडेयगंज मेट्रो स्टेशन, सिटी मेट्रो स्टेशन, मेडिकल चौराहा मेट्रो स्टेशन, चौक मेट्रो स्टेशन

परियोजना को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने में मदद

एमडी, यूपीएमआरसी सुशील कुमार ने बताया कि अंडरग्राउंड सेक्शन के इस प्रमुख सिविल टेंडर का जारी होना लखनऊ मेट्रो फेज-1बी परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। एलिवेटेड एवं अंडरग्राउंड दोनों सेक्शन पर समानांतर कार्य शुरू होने से परियोजना को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने में मदद मिलेगी। लखनऊ मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के पूरा होने पर चारबाग से वसंतकुंज तक तेज, सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा। इससे पुराने लखनऊ सहित घनी आबादी वाले क्षेत्रों को बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी, सड़क यातायात का दबाव कम होगा तथा शहर में टिकाऊ शहरी

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: एसआईटी को मिला 15 दिन का और वक्त, अब जांच का दायरा भी बढ़ेगा

एसआईटी अब नए सिरे से सभी बिंदुओं पर जांच कर विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी.

(जीएनएस)।

लखनऊः अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दानपात्र से सात करोड़ रुपये के चढ़ावे की चोरी के मामले में गठित विशेष जांच दल (रक्ळ) को जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का और समय दिया गया है. राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रक्ळ के कार्यकाल को बढ़ाया गया है. अब जांच का दायरा भी बढ़ाया जाएगा.

राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, यह मामला बीते जून में तब सुर्खियों में आया था जब विपक्षी दलों ने दानपात्र से चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाया था. उसके बाद 13 जून को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने

मुख्यमंत्री से पूरे मामले की रक्ळ से जांच कराने का अनुरोध किया था. सरकार ने तत्काल तीन सदस्यीय रक्ळ का गठन किया, जिसमें लखनऊ के मंडलायुक्त क्ळर विजय विश्वास पंत, आईजी रेंज क्ळर किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं.

शुरूआत में रक्ळ को 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट देने को कहा गया था, जिसमें सात दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट देनी थी. अब समय सीमा बढ़ने के बाद टीम मंदिर प्रशासन, चढ़ावा गिनने वाले करीब 50 कर्मचारियों और सीसीटीवी सिस्टम की बारीकी से पड़ताल करेगी. मंडलायुक्त मंदिर व्यवस्था, आईजी किरण एस पुलिसिया एंगल से चोरी की संभावना और नील रतन वित्तीय गड़बड़ी की जांच कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि रक्ळ जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और दोषी कोई भी हो, बचेगा नहीं. उन्होंने रामभक्तों से धैर्य रखने और दस्तावेजी सबूत रक्ळ को देने की अपील भी की थी.

प्रवक्ता ने कहा कि जांच का दायरा बढ़ाकर दान की पूरी प्रक्रिया, अकाउंट बुक और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से पूछताछ भी शामिल की जाएगी. रक्ळ अब नए सिरे से सभी बिंदुओं पर जांच कर 15 दिन में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी.

रामराज्य कोष लिखा संदूक का बरामद होना साजिश का संकेत

(जीएनएस)।

राम मंदिर गबन मामला एक संगठित अपराध जैसा सामने आ रहा है। आरोपी अविनाश शुक्ला जिस योग केंद्र में नौकरी करता था, वहां से बरामद रामराज्य कोष लिखा संदूक का बरामद होना यही बता रहा है।

अयोध्या के राम मंदिर चोरी मामले में शक की सुई आरोपी अविनाश शुक्ला पर जाकर ठहर गई है। मामले के मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला (जो जेल में बंद है) के ठिकानों पर पुलिसिया कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस ने उस योग केंद्र पर छापेमारी की जहां अविनाश शुक्ला रहता था। तलाशी के दौरान पुलिस ने योग केंद्र से एक संदूक बरामद किया है, जिस पर "रामराज्य कोष" लिखा हुआ है। इसमें कितनी नकदी मिली है, पुलिस ने जानकारी नहीं दी है। इस संदूक पर एक क्यू आर कोड भी छपा हुआ मिला है। पुलिस अब इस दफकोड से जुड़े बैंक खातों और इसके जरिए हुए सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री खंगाल रही है, ताकि अवैध रूप से जुटाए गए चंदे के मुख्य स्रोत का पता लगाया जा सके। पुलिस उस मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाहती है, जिसके कहने पर रामराज्य कोष बनाया गया।

अविनाश शुक्ला के इतिहास को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं, जो इस पूरी साजिश की गहराई को दर्शाती हैंः अविनाश मूल रूप से किसी दूसरे जिले का रहने वाला है। करीब डेढ़ साल पहले वह इस क्षेत्र में आया और इस योग केंद्र में पनाह ली। योग केंद्र में रहने के दौरान ही उसने योजनाबद्ध तरीके से राम मंदिर में नौकरी हासिल की। जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगा रही हैं कि एक बाहरी व्यक्ति को इतनी आसानी से मंदिर परिसर और चंदा प्रबंधन से जुड़ी नौकरी दिलाने में किन लोगों ने पैरवी की थी।

शुक्ला उन आरोपियों में शामिल है जिसे राम मंदिर में कैश गिनने के काम पर लगाया गया था। एसबीआई ने जब अविनाश शुक्ला समेत सभी 8 लोगों को हटाना चाहा तो राम मंदिर ट्रस्ट ने इन 8 लोगों को नहीं हटाने के लिए दबाव बनाया। अविनाश शुक्ला ही वो आरोपी है जिसके घर से 80 लाख रुपये बरामद किए गए।

मामले की गंभीरता और इसमें शामिल बड़े नेटवर्क को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे घोटाले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (रक्ळ) को और समय दे दिया है। रक्ळ को अब अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया गया है। माना जा रहा है कि इस बढ़ी हुई अवधि में रक्ळ वित्तीय हेरफेर और डिजिटल फॉरेंसिक साक्ष्यों को और मजबूत करेगी।

अयोध्या पुलिस ने चढ़ावे के प्रबंधन, दान की निगरानी व्यवस्था, कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया और बैंकिंग सिस्टम से जुड़े 70 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। इस नोटिस के जरिए उन सभी लोगों को जांच के दायरे में लाया गया है जिनकी जिम्मेदारी दान के पैसों की गिनती करने, उसे बैंक में जमा करने या सुरक्षा व्यवस्था को देखने की थी। पुलिस यह पता लगा रही है कि इतने लंबे समय तक इतनी बड़ी हेराफेरी बिना किसी आंतरिक मिलीभगत या बड़ी लापरवाही के कैसे चलती रही।

लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग गैंग का भंडाफोड़; फर्जी कॉल सेंटर पर छापा, 100 से ज्यादा लोग हिरासत में

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार का कहना है कि जांच के बाद नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जाएगी.

(जीएनएस)।

लखनऊ : राजधानी लखनऊ में पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की है. लखनऊ कमिश्नरेट की साइबर सेल और लखनऊ पुलिस की संयुक्त टीम ने गोमतीनगर स्थित समिट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा. पुलिस ने 119 लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने मौके से 100 लैपटॉप, 178 मोबाइल, कई डिजिटल उपकरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कॉल सेंटर के जरिए विदेशों के लोगों को निशाना बनाकर साइबर ठगी की जा रही थी.

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार का कहना है कि जब्त किए गए लैपटॉप, मोबाइल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच के बाद अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जाएगी. साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि इस गिरोह को आर्थिक लाभ किसे मिल रहा था और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क का खुलासा होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर के निर्देशन में की गई. संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार और पुलिस उपायुक्त अपराध अनिल कुमार यादव की निगरानी में साइबर सेल और साइबर थाना की टीम ने फर्जी कॉल सेंटर के बारे में जानकारी मिली थी जिसके बाद कार्रवाई की गई. पुलिस की जांच में सामने आया कि बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर दो अलग-अलग कार्यालयों से यह फर्जी कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था.

पुलिस की जांच में पता चला है कि यहां काम करने वाले लोग मुख्य रूप से रात के समय विदेशी नागरिकों को फोन करते थे. उन्हें तकनीकी समस्या, निवेश, डॉलर ऐप और अन्य तरह के प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाते थे. जिसके बाद अलग-अलग तरीकों से उनसे पैसे ठगे जाते थे. पुलिस को आशंका है कि इस नेटवर्क के तार देश के बाहर तक जुड़े हो सकते हैं.

पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने मूलरूप से अहमदाबाद (गुजरात) के रहने वाले ललित खैराजानी और वर्तमान में गोमती नगर विस्तार में रह रहे विक्रम सिंह परमार को भी हिरासत में लिया है. दोनों आरोपी वर्तमान में गोमती नगर में रह रहे थे. दोनों कॉल सेंटर में ऑपरेशन मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे. पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है.

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

उच्च न्यायालय मद्रास का बड़ा फैसला अब धर्म परिवर्तन केक बाद भी आरक्षण का लाभ लेना हुआ असम्भव

यह उपाय आरक्षण के मूल उद्देश्य के विरुद्ध होने के साथ संविधान के साथ धोखाधड़ी है। यह उपाय आरक्षण नीति के मौलिक सामाजिक लक्ष्यों को कमजोर करता है। अतएव ऐसे उपाय हासिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के उद्देश्य के तहत आरक्षण नीतियों की मूल भावना के विपरीत हैं।

उच्च न्यायालय मद्रास ने तमिलनाडू सरकार के उस अहम् आदेश को रदद् कर दिया,जिसके तहत हिदू धर्म के पिछड़े,अति पिछड़े या अनुसूचित जाति वर्ग के लोग इस्लाम अपनाने के बाद भी पिछड़े वर्ग मुस्लिमका जाति प्रमाण पत्र ले सकते थे। सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण पा लेने की इस सुविधा को न्यायालय ने दो टूक शब्दों में असंवैधानिक माना है। अदालत ने कहा कि धर्म बदलने वाला व्यत्ति पिछड़ा वर्ग मुस्लिमका दर्जा मांगने का अधिकार नहीं रखता है। क्योंकि मुस्लिम समाज में भी अलग-अलग समुदाय और वर्ग होते हैं,परंतु उनकी पहचान जन्म से तय होती है न कि धर्म परिवर्तन से? अदालत ने यह भी कहा कि इस्लामिक उपदेशक और ईसाई मिशनरियां सदियों से यह प्रचार करती आई हैं कि उनके धर्मो में सामाजिक समानता है,जबकि हिदू धर्म में जाती व्यवस्था एक बुनियादी विसंगति है। अतएव धर्म परिवर्तन के लिए ऐसा रुख अपनाने के बाद यह कहना बेमानी है कि इस्लाम में भी ऊंच-नीच या वर्गभेद है। हमारी राय में वुछ मुस्लिम समुदायों को पिछड़ा और वुछ को अगड़ा मानना वुरान की शिक्षाओं के खिलाफ है। दरअसल इस्लाम एक ऐसा समाज बनाना चाहता है, जिसमें सब का दर्जा एक समान रहे। यह ऐतिहासिक पैसला न्यायामरूति जीआर स्वामीनाथन और पीबी बालाजी की पीठ ले दिया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकताओं ने तमिलनाडू सरकार के तीन मार्च 2024 के आदेश को आधार बनाया था। जिसमें आरक्षित श्रेणियों से धर्मातरित लोगों को तमिलनाडू में अधिसूचित सात पिछडे वर्ग के मुस्लिम समूहों में से एक से संबंधित होने का सामुदायिक प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता था। सरकार ने अपने आदेश में यह प्रविधान किया था कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग,अत्यंत पिछड़ा वर्ग या डी-नोटिफाइड समुदायों से आने वाले व्यत्ति यदि इस्लाम धर्म अपनाते हैं तो उन्हें पिछड़ा वर्ग मुस्लिम की क्षेणी में आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। इस सिलसिले में सरकार का तर्व था कि धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और सामाजिक संतुलन बना रहेगा। कितु अदालत ने कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि, सामाजिक और षैक्षिक पिछड़ापन है। इसी से मिलती-जुलती प्रवृति के एक एक मामले में पैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि बिना किसी वास्तविक आस्था के केवल आरक्षण के लाभ हेतु किया गया धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखाधड़ी है। सी सेल्वरानी की याचिका पर 26 नवंबर 2024 को पैसला सुनाते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय के 24 नवंबर के उस पैसले को बरकरार रखा,जिसमें ईसाई धर्म अपना चुकी एक महिला को अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर दिया गया था। महिला ने बाद में आरक्षण के तहत रोजगार का लाभ प्राप्त करने के लिए हिदू होने का दावा किया था। लेकिन इस पीठ ने पैसले में साफ किया कि कोई व्यत्ति किसी अन्य धर्म को तभी अपनाता है, जब वह वास्तव में उसके सिद्धांतों और धर्म आधारित आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित होता है। यदि धर्म परिवर्तन का मकसद दूसरे धर्म में वास्तविक आस्था होने की बजाय आरक्षण का लाभ प्राप्त करना है तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसी गलत इच्छा रखने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ देने से आरक्षण नीति के सामाजिक व्यवहार को क्षति पहुंचेगी। बावजूद सेल्वरानी हिदू होने का दावा करती है और नौकरी के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र मांगती है,तब यह दोहरा दावा अस्वीकार्य है। साफ है,वह ईसाई धर्म अपनाने के बावजूद एक हिदू के रूप में अपनी पहचान नहीं बनाए रख सकती हैं। संविधान के तीसरे अनुच्छेद, अनुसूचित जाति आदेश 1950 जिसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है,के अनुसार केवल हिदू धर्म का पालन करने वालों के अतिरित्त किसी अन्य व्यत्ति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इसी तारतम्य में पिछले 50 सालों से दलित ईसाई और दलित मुसलमान संघर्षरत रहते हुए हिदू अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले अधिकारों की मांग करते चले आ रहे हैं।

'ब्यूरोक्रेटिक साइलो' खत्म करने के निर्देश, पीएम मोदी का 'गतिशक्ति मास्टर प्लान' क्या है? समझें क्यों जरूरी है

(जीएनएस)।

पीएम मोदी ने केंद्रीय सचिवों के साथ एक लंबी बैठक में सरकारी विभागों के बीच काम के बंटवारे (ब्यूरोक्रेटिक साइलो) को खत्म करने और 'आत्मनिर्भरता' को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने इस तालमेल को हासिल करने के लिए 'पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान' के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की भी बात कही। जान लीजिए ये क्यों है जरूरी।

सचिवों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कह दी बड़ी बात

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 'सेवा तीर्थ' में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों संग हाईलेवल मीटिंग की। करीब चार घंटे चली इस मैराथन बैठक में सुधार एजेंडे पर व्यापक चर्चा पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विभागों के बीच बनी रुकावटों (ब्यूरोक्रेटिक साइलो) को खत्म करें और सरकारी योजनाओं के खास असर पर पूरा ध्यान दें। इस अहम बैठक में भारत के लगभग 80 शीर्ष अधिकारी शामिल हुए।

सचिवों के साथ पीएम मोदी ने की मैराथन बैठक

सरकार लगातार अगली पीढ़ी के प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ा रही है। इस बैठक में मुख्य रूप से 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस', डिजिटल गवर्नेंस, नियमों में ढील और 'लास्ट-माइल डिलीवरी' जैसे विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान कैबिनेट सचिव के अलावा बैठक में प्रधानमंत्री के दो प्रधान सचिव, पी.के. मिश्रा और शक्तिकांत दास और सभी प्रमुख विभागों के सचिव भी मौजूद रहे।

अलग-अलग प्रशासनिक सीमाओं से ऊपर उठने के निर्देश

केंद्रीय सचिवों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी मंत्रालयों को अपनी अलग-अलग प्रशासनिक सीमाओं से ऊपर उठकर एक एकीकृत और 'पूरे सरकार' वाले नजरिए को अपनाना चाहिए। इस तालमेल को हासिल करने के लिए, उन्होंने 'पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान' के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की पुरजोर वकालत की।

गतिशक्ति मास्टर प्लान से बदलेंगे हालात

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर टूल के तौर पर नहीं, बल्कि डेटा-आधारित और विभागों के बीच तालमेल बिठाने वाले एक जरूरी जरिया के तौर पर पेश किया। जो रुके हुए फैसलों में तेजी ला सकता है। ये अलग-अलग सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट्स को सुचारू बना सकता है।

कबाबों और नवाबों का शहर लखनऊ अब नया पार्टी कैपिटल बन गया है

समिट बिल्डिंग ने लखनऊ को नोएडा के बाहर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नाइटलाइफ डेस्टिनेशन बना दिया. इसने शहर के पार्टी कल्चर—और उससे जुड़ी समस्याओं—को भी एक ही जगह पर समेट दिया.

(जीएनएस)।

लखनऊः लखनऊ के विभूति खंड में शुक्रवार की रात, पार्टी शुरू होने से पहले ही पुलिस पहुंच जाती है.

कुछ साल पहले, लखनऊ में ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल था—एक ऐसा शहर जिसकी पहचान तहजीब, कबाब और पुराने जमाने के आकर्षण से थी, न कि नाइटलाइफ से. फिर भी आज, पुलिस की मौजूदगी उस जगह का हिस्सा बन गई है जो शायद नोएडा के बाहर उत्तर प्रदेश का सबसे मशहूर नाइटलाइफ डेस्टिनेशन बन गया है.

बहुत से लोगों के लिए, लखनऊ में क्लबिंग का मतलब समिट बिल्डिंग है. 17 मंज़िल इस बिल्डिंग का उद्घाटन आधिकारिक तौर पर 2019 में हुआ था. उद्घाटन से पहले भी वहाँ रेस्टोरेंट चल रहे थे, लेकिन 2019 तक लगभग हर मंज़िल पर एक नाइटक्लब खुल गया था.

आज, समिट के अंदर हर क्लब एक ही तरह के माहौल में चलता हैः अंधेरे कमरे, काली दीवारें, नीची छतें और हल्की रोशनी वाले बूथ. लेजर इक्विपमेंट के अलावा कुछ भी चमकदार नहीं होता; ये इक्विपमेंट ज्यादातर खाली फ़्लोर पर इलेक्ट्रिक ब्लू, नियॉन पिंक और हरी रोशनी डालते हैं—यह खालीपन बताता है कि बिल्डिंग अब कैसी हो गई है. लेकिन इन डांस फ़्लोर ने बेहतर दिन भी देखे हैं.

शाम 7 बजे तक, डांस फ़्लोर किसी वेटिंग रूम की तरह दिखते हैं. कुछ लोग जो जल्दी आ जाते हैं, वे अपनी टेबल पर ड्रिंक्स का मजा लेते हैं. कोई नाच नहीं रहा होता, लेकिन ऊख अपना काम शुरू कर चुका होता है. संगीत ठीक सात बजे शुरू हो जाता है, चाहे कोई सुन रहा हो या नहीं. लाइटें भी उसी समय जल उठती हैं.

बाहर, रात का एक और रूटीन शुरू हो रहा होता है.

रात 11:30 बजे तक, एंट्री गेट पर पुलिस की गाड़ी खड़ी हो जाती है. वर्दी पहने पुलिसकर्मी बिल्डिंग के बाहर अपनी जगह ले लेते हैं. प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हर मंज़िल के कॉरिडोर में घूमते रहते हैं. कुछ लोग पार्किंग एरिया के पास रहते हैं और गाड़ियों के आने जाने पर नजर रखते हैं. यह तैनाती अब एक रूटीन बन गई है.

लखनऊ के सबसे व्यस्त नाइटलाइफ हब में वीकेंड की भीड़ को संभालने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समिट बिल्डिंग परिसर

में स्थित विभूति खंड पुलिस चौकी के बाहर पुलिसकर्मी जमा हुए हैं` फोटोः निकिता आरती नवीन/दिप्रिंट

युवा प्रोफेशनल, कॉलेज के छात्र, कपल्स और दोस्तों के ग्रुप अलग अलग मंज़िलों पर घूमते हैं और तय करते हैं कि शाम कहां बितानी है. हर क्लब के दरवाजे पर तैनात बाउंसर अंदर आने वाले संभावित ग्राहकों का स्वागत करते हैं. बॉलीवुड रीमिक्स की आवाज हॉलवे तक आती है. एक मैकडॉनल्ड्स देर रात तक ऑर्डर सर्व करता है. एक 'एनीटाइम फि टनेस' जिम चौबीसों घंटे खुला रहता है. ऑफि स में लाइटें जलती रहती हैं, और किराएदार जरूरत पड़ने पर आम कामकाजी घंटों के बाद भी काम कर सकते हैं. हालांकि, क्लबों को आधी रात तक बंद करना जरूरी होता है. यह पाबंदी सालों की शिकायतों, नगर निगम की छापेमारी, वायरल वीडियो, झगड़ों और निवासियों के बढ़ते दबाव के बाद लगाई गई है. निवासियों का कहना है कि शहर की सबसे मशहूर पार्टी डेस्टिनेशन अब अव्यवस्था का पर्याय बन गई है.

आज 'समिट' एक सफल कहानी भी है और एक सबक भी. समिट बिल्डिंग ने लखनऊ की नाइटलाइफ को कैसे बदला

द समिट बिल्डिंग ने लखनऊ के बहुत से लोगों को यह सिखाया कि पार्टी में जाना क्या होता है. इसने नाइटलाइफ को लोकतांत्रिक बनाने में मदद की, इसे उन हजारों युवाओं के लिए सुलभ बनाकर जिन्होंने पहले कभी नाइटक्लब में कदम नहीं रखा था. इसने एक टियर-दो शहर के मनोरंजन के साथ संबंध को बदल दिया.

लेकिन इसे कभी भी शहर के नाइटलाइफ के पते के रूप में बनने के लिए नहीं बनाया गया था.

विभूति खंड में स्थित, जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, स्कूलों और परिवारों के घरों वाला एक अपस्केल नियोजित इलाका है, यह बिल्डिंग मूल रूप से तेजी से विस्तार कर रहे लखनऊ की आकांक्षाओं को दशार्ती थी.

ऋ्ळ रोड और बार्बेक्यू नेशन जैसे रेस्टोरेंट्स परिवारों को वीकेंड लंच के लिए आकर्षित करते थे. ऑफिस जाने वाले लोग काम के बाद यहां रुकते थे. वही बिल्डिंग जो रात में नाइटक्लब की भीड़ से भर जाती थी, दिन में परिवारिक आउटिंग्स की मेजबानी करती थी और को-वर्किंग स्पेसेस की जरूरतें पूरी करती थी.

फिर लखनऊ ने बड़े पैमाने पर पार्टी करना खोज लिया. लखनऊ के विभूति खंड में स्थित समिट बिल्डिंग में रेस्टोरेंट, क्लब, कैफे और कॉर्पोरेट ऑफि स हैं। पिछले एक दशक में, यह शहर का सबसे मशहूर नाइटलाइफ डेस्टिनेशन बन गया है

जैसे-जैसे मिक्स्ड-यूज कमर्शियल टावर के अंदर फ्लोर दर फ्लोर क्लब्स बढ़ते गए, वैसे-वैसे भीड़ भी बढ़ती गई. शहर का बढ़ता हुआ मिडिल क्लास, छात्र, युवा प्रोफेशनल्स और पड़ोसी जिलों से आने वाले विज़िटर्स सभी समिट तक पहुंचने लगे. वीकेंड पर, एक पूरा नाइटलाइफ इकोसिस्टम एक ही बिल्डिंग के अंदर दिखाई देने लगा.

लेकिन एक ही जगह पर कई क्लब्स का यह केंद्रीकरण, जिसने समिट को सफल बनाया, उसे कमजोर भी बनाता था.

जब किसी एक क्लब के अंदर कुछ गलत होता था, तो वह शायद ही उसी क्लब तक सीमित रहता था. एक फ्लोर पर हुई लड़ाई कुछ ही घंटों में 'समिट' की कहानी बन जाती थी. और क्योंकि यह टावर एक रेजिडेंशियल इलाके के बीच में स्थित था, जो बालकनियों और अपार्टमेंट की खिड़कियों से दिखाई देता था, हर नाइटलाइफ विवाद जल्दी ही रेजिडेंशियल शिकायत बन जाता था.

आधिकारिक शिकायतों या पुलिस रिपोर्टों के सामने आने से बहुत पहले, क्लब्स के अंदर लड़ाइयों और टकरावों के वीडियो हैं३२अस्रस्र ग्रुप्स और सोशल मीडिया फीड्स में घूम रहे थे. धीरे-धीरे, 'समिट' का मतलब एक ऐसी बिल्डिंग होना बंद हो गया जिसमें रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, एक जिम और एक टूऊ्ल्लं'ी'२ था. यह नाइटलाइफ के लिए—और उससे जुड़ी समस्याओं के लिए एक शॉर्टहैंड बन गया.

नतीजा एक ऐसा सोशल एक्सपेरिमेंट था जो बहुत अच्छी तरह काम करता रहा, जब तक कि उसने काम करना बंद नहीं कर दिया.

समिट बिल्डिंग की डायरेक्टरी में रेस्टोरेंट, बार, क्लब, ऑफिस और कॉर्पोरेट किराएदारों की लिस्ट है, जो लखनऊ की सबसे व्यस्त मिक्स्ड-यूज जगहों में से एक के तौर पर इसके विकास को दिखाती है` फोटोः निकिता आरती नवीन/दिप्रिंट

'समिट' लखनऊ के लिए पुलिसिंग की सबसे बड़ी चुनौती बना

नाइटलाइफ के मशहूर ठिकाने से पुलिसिंग की चुनौती बनने तक का यह सफर रातोंरात तय नहीं हुआ. यह कई सालों में, एक एक करके हुई घटनाओं के जरिए हुआ.

मई 2021 में, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें इमारत के एक क्लब के अंदर महिलाओं का एक ग्रुप एक दूसरे के पीछे भागता, मुक्के मारता और एक दूसरे को जमीन पर पटकता हुआ दिखा; वे अलग होतीं और फिर से एक दूसरे का पीछा करने लगतीं. वीडियो में पुलिस अफसर भी दिखे जो लड़ाई वाली जगह के पास ही खड़े थे. यह फुटेज इतनी तेजी से फैल गई कि एक ही दिन में पूरे शहर में इसकी चर्चा होने लगी.

गलत वजहों से इस इमारत के सुर्खियों में आने का यह आखिरी मामला नहीं था.

2022 तक, दैनिक जागरण ने रिपोर्ट किया कि 'समिट' 'अराजकता का अड्डा' बन गया था, जहाँ बार चलाने वाले खुलेआम नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे थे, नाबालिग शराब पीते हुए देखे जा रहे थे, और महिलाओं के साथ मारपीट और उत्पीड़न के मामले आम हो गए थे.

सितंबर 2025 में, एक ही रात हुई दो अलग अलग घटनाओं के कारण दो पुलिस अफसरों को अपनी पोस्टिंग गंवानी पड़ी. काम से लौट रहे एक नाइटक्लब पीआर मैनेजर को गोली मारे जाने और एक मारपीट की घटना (जिसका वीडियो वायरल हुआ था) के बाद विभूति खंड के एसएचओ और समिट बिल्डिंग आउटपोस्ट के इंचार्ज को हटा दिया गया.

इससे तीन दिन पहले ही, इलाके की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इन दोनों घटनाओं से परे कई शिकायतें दर्ज कराई थींः शोर शराबा, पार्किंग में जाम और इलाके की कार पार्किंग से बाहर तक शराब पीकर गाड़ी चलाने की समस्या.

कुछ दिनों बाद, लखनऊ पुलिस और आबकारी विभाग ने इलाके में संयुक्त निगरानी शुरू की और वीकेंड की रातों में 11:30 बजे के बाद इमारत के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया. दिसंबर तक, नगर निगम ने 'समिट' पर छापा मारा और कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में इमारत के कुछ हिस्सों को सील कर दिया.

तब से, पुलिसकर्मी रात करीब 2 बजे तक 'समिट' के अंदर तैनात रहते हैं, और अब इमारत के अंदर ही एक स्थायी पुलिस आउटपोस्ट काम करता है.

लेकिन अपराध और विवाद कभी पूरी तरह बंद नहीं हुए.

ऋ्ळ रोड और बार्बेक्यू नेशन जैसे रेस्टोरेंट वीकेंड पर लंच के लिए परिवारों को आकर्षित करते थे. ऑफिस जाने वाले लोग काम के बाद यहाँ रुकते थे. वही बिल्डिंग, जो रात में नाइटक्लब की भीड़ से भर जाती थी, दिन में परिवारों के घूमने फिरने और को वर्किंग स्पेस के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी.

फिर लखनऊ को बड़े पैमाने पर पार्टी करने का चस्का लगा.

इस साल जनवरी में, एक बिजनेसमैन को एक रवश ने टक्कर मार दी और वह लगभग 25 मिनट तक बिल्डिंग की पार्किंग में गाड़ी के पहियों के नीचे फंसा रहा. उसने तब बीच बचाव करने की कोशिश की थी जब उत्तराखंड के कुछ युवाओं का एक ग्रुप, जो रवश में था, दूसरी कार में सवार लोगों से झगड़ रहा था. लेकिन आरोप है कि उस ग्रुप ने उसे गाड़ी से कुचल दिया और उसे गाड़ी के नीचे फंसा हुआ छोड़ दिया.

इस साल 26 मई को, भारतीय जनता युवा मोर्चा के 28 साल के एक नेता के साथ एक नाइटक्लब के बाहर मारपीट हुई; यह झगड़ा कथित तौर पर सिगरेट को लेकर शुरू हुआ था. तीन दिन बाद, चोटों के कारण उनकी मौत हो गई. अगले वीकेंड तक, इलाके के अउढ और रलड का फिर से ट्रांसफर कर दिया गया.

इन बार बार होने वाली घटनाओं ने एक बड़ी समस्या को उजागर किया. समिट की मुश्किलें कभी भी सिर्फ अलग अलग क्लबों तक सीमित नहीं थीं; इनकी जड़ शहर की ज्यादातर नाइटलाइफ को एक ही बिल्डिंग में समेटने में थी.

एक ही बिल्डिंग में दर्जन भर नाइटक्लब, रेस्टोरेंट और ऑफि स स्पेस बना दिए जाएं. लखनऊ और आसपास के ज़िलों से लोगों को एक ही पते पर बुलाया जाए. हर रात लगभग एक ही समय पर सैकड़ों लोग सड़कों, सीढ़ियों, लिफ़्ट और पार्किंग लॉट में उमड़ पड़ते हैं. तब वह बिल्डिंग नाइटलाइफ डेस्टिनेशन की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेशर सिस्टम की तरह काम करने लगती है. किसी एक जगह पर हुआ मामूली झगड़ा भी तेजी से कॉरिडोर तक फैल सकता है.

यह कहानी है कि कैसे लखनऊ ने रातोंरात पार्टी कल्चर बनाया, कैसे वह कल्चर उस बिल्डिंग से बड़ा हो गया जिसमें वह फला फूला, और कैसे पार्टी पसंद करने वाला एक टियर 2 शहर अभी भी इसे सही ढंग से करना सीख रहा है.

समिट से पहलेः लखनऊ का पुराना क्लब कल्चर लखनऊ के बाहर आम धारणा यह है कि नाइटलाइफ यहां हाल ही में आई है.

हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कहते हैं कि यह बात सिर्फ. आंशिक रूप से सच है. समिट के बनने से बहुत पहले ही शहर में पार्टी कल्चर मौजूद था.

वहां होटल क्लब, सिर्फ.मेंबर्स के लिए बनी जगहें और अलग-अलग इलाकों में फैली नाइटलाइफ की जगहें थीं. भीड़ कम होती थी, ज्यादा एक्सक्लूसिव होती थी और अक्सर लोग एक-दूसरे को जानते थे.

'माई बार हेडक्वार्टर्स' के रेस्टोरेंट मैनेजर वासी हैदर ने कहा, 'मैं 18 साल से क्लबिंग सीन से जुड़ा हूं. उस समय जीरो डिग्री और ब्लू जैसे क्लब मशहूर थे. वहीं से इसकी शुरूआत हुई थी.'

पुराने क्लब भी अलग तरह के होते थे. उन्होंने कहा, 'ज्यादातर क्लबों का अंदर का माहौल अंधेरा होता था, एक बड़ा हॉल होता था, सोफे लगे होते थे और जोरदार म्यूज़िक बजता था. आज के क्लबों का डिजाइन अलग है, साउंड सिस्टम बेहतर हैं, खुली छतें हैं और माहौल भी बिल्कुल अलग है.'

2000 के दशक के ज्यादातर समय और 2010 के शुरूआती सालों में, क्लब जाना मुख्य रूप से अमीर लोगों की ही गतिविधि थी.

हैदर ने कहा, 'उस समय, अपर-मिडल क्लास के लोग भी क्लब आने से डरते थे. उन्हें पता नहीं होता था कि उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा या नहीं.'

वहीं दूसरी ओर, जेनेसिस और चांसलर्स क्लब जैसे क्लबों में परिवार इकट्ठा होते थे. बच्चे खेलते थे और बड़े लोग आपस में घुलते-मिलते थे. म्यूज़िकल शामें, कम्युनिटी इवेंट और वीकेंड पर लोगों का मिलना-जुलना आम बात थी.

मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई में काम करने के बाद शहर लौटीं एक महिला को वे दिन बहुत अच्छे से याद हैं. उन्होंने कहा, 'वहां हमेशा कोई न कोई अच्छा म्यूज़िकल इवेंट होता रहता था. तीन-चार जोड़ों का ग्रुप इकट्ठा होता था और बच्चे एक कोने में खेलते थे. यह एक अच्छा और सुखद अनुभव होता था.'

उन्हें आज की नाइटलाइफ अलग लगती है. 'मजे करने का तरीका बदल गया है. अब यह ज्यादातर EDM म्यूज़िक, देर रात तक जागने और शराब पीने के बारे में है.

द्वारका एक्सप्रेसवे (एनएच 248 बीबी) को दिल्ली के वसंत कुंज स्थित नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ने के इंतजाम की तैयारी

कैबिनेट ने एनएच (ओ) योजना के अंतर्गत हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) पर 6969.67 करोड़ रुपये की लागत से 8.1 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 6 लेन की सुरंग के निर्माण को स्वीकृति दी, यह सुरंग द्वारका एक्सप्रेसवे (एनएच 248 बीबी) को दिल्ली के वसंत कुंज स्थित नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने आज एनएच (ओ) योजना के अंतर्गत हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएम) पर द्वारका एक्सप्रेसवे (एनएच 248 बीबी) को नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, दिल्ली से जोड़ने वाले एनएच-148एई के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण को स्वीकृति दी है। इस परियोजना की कुल लंबाई 8.1 किलोमीटर और कुल पूंजी लागत 6969.67 करोड़ रुपये है।

यह परियोजना पश्चिम और दक्षिण दिल्ली के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करेगी, जिससे यूईआर 2/द्वारका एक्सप्रेसवे दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज से जुड़ जाएगा। इसके अतिरिक्त, गुरुग्राम, द्वारका, आईजीआई हवाई अड्डे और पश्चिम दिल्ली से दक्षिण दिल्ली की ओर जाने वाले यातायात को भी लाभ मिलेगा। भूमिगत दोहरी सुरंग से सतह पर यातायात व्यवधान कम से कम होगा और दक्षिणी रिज वन (सुरंग का 1.98 किमी भाग रिज के नीचे से गुजरता है) संरक्षित रहेगा। एनएचएआई एम्स और महिपालपुर के बीच एक एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव कर रहा है। यह लिंक सुरंग को बारापुल्ला एलिवेटेड रोड से जोड़ेगा, जिससे पश्चिम दिल्ली और दक्षिण दिल्ली पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा से जुड़ जाएंगे।

प्रस्तावित सुरंग रंगपुरी (दक्षिणी दिल्ली) रिज से होकर गुजरती है, जिसे एक ट्विन-ट्यूब सुरंग (टीबीएम के माध्यम से निर्मित की जाएगी) के रूप में डिजाइन किया गया है, यह शिवमूर्ति इंटरचेंज से शुरू होती है और नेल्सन मंडेला मार्ग और महिपालपुर छतरपुर रोड के चौराहे से पहले समाप्त होती है।

इस चौराहे पर भीड़भाड़ कम करने के लिए नेल्सन मंडेला मार्ग के समानांतर एक एलिवेटेड रोड (1.8 किमी) प्रस्तावित है। छतरपुर से महिपालपुर की ओर वर्तमान फ्लाईओवर के समानांतर एक अतिरिक्त फ्लाईओवर भी प्रस्तावित है। छतरपुर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए दाएं मुड़ने की सुविधा हेतु एक एलिवेटेड यू-टर्न भी प्रस्तावित है।

मुख्य कैरिजवे की लंबाई 6.3 किमी है। महिपालपुर छतरपुर रोड पर प्रस्तावित फ्लाईओवर और एलिवेटेड यू टर्न को ध्यान में रखते हुए, परियोजना की कुल लंबाई 8.100 किमी है, जिसमें 3.140 किमी सुरंग, 0.980 किमी सुरंग अप्रोच रैंप, 0.554 किमी आरई वॉल के साथ अप्रोच, 2.556 किमी एलिवेटेड भाग और 0.870 किमी एट-ग्रेड सड़क शामिल है।

अनुमान है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रत्येक लेन-किलोमीटर के विकास से औसतन 264 व्यक्ति-दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और औसतन 55 व्यक्ति-दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होता है।

लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा ने दक्षिण पश्चिमी कमान का कार्यभार संभाला

(जीएनएस)।

लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा, एवीएसएम, एसएम ने दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ का पदभार ग्रहण कर लिया है।

जून 1989 में 47 बख्तरबंद रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त करने वाले जनरल ऑफिसर के पास 37 वर्षों से अधिक का विशिष्ट सेवा का अनुभव है, जिसमें कमान, स्टाफ और प्रशिक्षण संबंधी सभी महत्वपूर्ण स्तरों पर कार्य शामिल हैं। कार्यभार संभालने से ठीक पहले उन्होंने पूर्वी कमान मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने संचालन संबंधी तत्परता, संगठनात्मक प्रभावशीलता और संस्थागत सामंजस्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

उनके कमान अनुभव में सेना के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण परिचालन शामिल हैं, जिनमें सियाचिन ग्लेशियर, बख्तरबंद रेजिमेंट, स्वतंत्र बख्तरबंद ब्रिगेड, बख्तरबंद डिवीजन और रेगिस्तान कोर शामिल हैं। इन नियुक्तियों ने उन्हें विभिन्न मोर्चों पर जटिल बहु-क्षेत्रीय अभियानों की संचालन योजना और संचालन में व्यापक विशेषज्ञता प्रदान की है। उनके पास कमान के अलावा संचालन योजना, सैन्य खुफिया, संचालन रसद, कार्मिक प्रबंधन, प्रौद्योगिकी अपनाने और रणनीतिक संवाद सहित प्रमुख स्टाफ पदों पर कार्य करने का व्यापक सैन्य अनुभव है।

लेफ्टिनेंट जनरल मल्होत्रा एक उच्च कोटि के विद्वान-सैनिक हैं। उनके पास रक्षा अध्ययन में दो स्नातकोत्तर डिग्रियां हैं, जिनमें एक किंग्स कॉलेज, लंदन की डिग्री शामिल है। इसके अलावा, उनके पास राजनीति विज्ञान और रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में दो एमफिल डिग्रियां भी हैं। उन्होंने अपने सभी पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और लगभग सभी पाठ्यक्रमों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जनरल ऑफिसर यूनाइटेड किंगडम के एडवांस्ड कमांड एंड स्टाफ कोर्स, हायर एयर कमांड कोर्स और नेशनल डिफेंस कॉलेज से स्नातक हैं।

लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा को राष्ट्र के प्रति उनकी विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक और सेना पदक से सम्मानित किया गया है। उन् हें सेना कमांडरों और सेना प्रमुख से कई प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुए हैं।

लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा के नाम उत्कृष्ट संचालन क्षमता, रणनीतिक स्पष्टता और संस्थागत नेतृत्व का एक स्थापित रिकॉर्ड है। रणनीतिक रूप से सबसे अधिक महत् वपूर्ण कमानों में से एक का इनका नेतृत् व भारतीय सेना को राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध बनाता है।

भारत पहुंचीं जापानी पीएम सनाए तकाईची: हिंद-प्रशांत क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा पर पीएम मोदी संग करेंगी मंथन

जापानी पीएम सनाए तकाईची भारत पहुंचीं, पीएम मोदी से मिलेंगी।

16वें भारत-जापान शिखर सम्मेलन में हिंद-प्रशांत पर चर्चा।

आर्थिक सुरक्षा, निवेश, सेमीकंडक्टर, एआई सहयोग मुख्य एजेंडा।

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची बुधवार देर शाम नई दिल्ली पहुंची। गुरुवार को उनकी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर बैठक होगी। दोनों नेता 16वें भारत-जापान सालाना सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, जिसे मौजूदा वैश्विक उथल-पुथल के बीच बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत रवाना होने से पहले जापानी प्रधानमंत्री ने कहा था, 'अंतरराष्ट्रीय स्थिति तेजी से अनिश्चित होती जा रही है, ऐसे समय में जापान के साथ मौलिक मूल्यों और सामरिक हितों को साझा करने वाले भारत के साथ सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इस यात्रा के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ आर्थिक सुरक्षा, निवेश और नवाचार के क्षेत्र में ठोस सहयोग को आगे बढ़ाना चाहती हूं।'

प्रधानमंत्री तकाईची ने भारत पहुंचते ही कहा कि जापान-भारत संबंधों को और मजबूत करना उनका मुख्य उद्देश्य है। यह दौरा फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने वाला साबित होगा।

जापानी पीएम के इस बयान को अमेरिकी सरकार के इस ताजे फैसले

से जोड कर देखा जा रहा है जिसमें अमेरिकी सैन्य कमांड के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र का नाम बदल कर सिर्फ पैसिफिक कमांड कर दिया गया है।

जानकारों के मुताबिक, मोदी और तकाईची के बीच होने वाली बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर खास तौर पर बात होगी। नई वैश्विक व्यवस्था में अमेरिकी नीति में जिस तरह से हिंद प्रशांत को लेकर अस्पष्टता दिख रही है उसको देखते हुए जापान व भारत की आपसी रणनीति क्या होगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर होगी।

गुरूवार को होने वाली शिखर वार्ता में दोनों नेता द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें जापान की तरफ से भारतीय बाजार में 10 अरब येन निवेश एक बड़ा एजेंडा होगा। बैठक में उन क्षेत्रों का चयन होगा जहां यह निवेश किया जाना है।

दूसरा एजेंडा, समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता (सीपा) को लेकर चल रही वाताओं की समीक्षा और आगे की दिशा होगी। साथ ही जापान की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षित भारतीय कामगारों को भेजने पर भी बात होनी है। दोनों देशों के बीच पहले ही पांच वर्षों में पांच लाख भारतीय प्रशिक्षित कामगारों को जापान भेजने की सहमति बनी है। हालांकि अभी इसमें खास प्रगति नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं की तरफ से इस पर और बात होगी।

सेमीकंडक्टर उद्योग व एआइ सहयोग दो अन्य क्षेत्र हैं जो भारत व जापान के संबंधों को दिशा देने वाले हैं। पिछले तीन-चार वर्षों में दोनों देशों ने आर्थिक सुरक्षा, दुर्लभ खनिजों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर मजबूत सहयोग का ढांचा तैयार किया है।

आर्थिक सुरक्षा वार्ता नवंबर 2024 में टोक्यो में शुरू हुई थी जिसमें सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और आईसीटी को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया।

इसके तहत दूसरी वार्ता मई 2026 में नई दिल्ली में हुई है। इसी तरह से अगस्त, 2025 में दुर्लभ खनिज संसाधनों पर समझौता हुआ है। इसकी पहली संयुक्त कार्य दल की बैठक अप्रैल 2026 में संपन्न हुई है जबकि जुलाई 2023 में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन विशेष बैठक की शुरूआत हो चुकी है और अब जापान की कंपनियों ने भारत में प्लांट लगाने की शुरूआत भी कर दी है।

अप्रैल, 2026 में एआई सहयोग पर भी दोनों देशों में पहली बैठक हुई और अब इसे आगे ले जाने को लेकर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की तरफ से गुरुवार को निर्देश मिलने की संभावना है।

पीएम मोदी ने जापान कीं प्रधानमंत्री का किया गर्मजोशी से स्वागत

जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची तीन दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया. दोनों नेता व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, तकनीक और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी और ताकाइची 16वीं भारत-जापान वार्षिक शिखर बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे.

व्यापार, रक्षा, ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर सहयोग प्रमुख एजेंडा रहेगा.

दोनों देशों के बीच कई नए समझौतों और निवेश प्रस्तावों की घोषणा संभव है.

(जीएनएस)। भारत और जापान के रिश्तों को नई मजबूती देने के मकसद से जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची तीन दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देश मिलकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करेंगे. ये ताकाइची की प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली आधिकारिक भारत यात्रा है, इसलिए इसे दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.

इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारत-जापान की 16वीं वार्षिक शिखर बैठक है, जिसकी संयुक्त अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सानाए ताकाइची करेंगे. इस बैठक में दोनों देश अब तक हुए सहयोग की समीक्षा करेंगे और भविष्य की साझेदारी का नया रोडमैप तैयार करेंगे. बैठक के बाद साझा बयान जारी होने की भी संभावना है.

दोनों नेताओं के बीच व्यापार और निवेश प्रमुख एजेंडा रहेगा. भारत और जापान सेमीकंडक्टर, बैटरी निर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार करेंगे. माना जा रहा है कि इन क्षेत्रों में कई नए समझौतों पर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं.

ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा भी इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. ओडिशा में प्रस्तावित ग्रीन अमोनिया परियोजना, बायोगैस सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े नए निवेश प्रस्तावों पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा होने की संभावना है. इसके अलावा सप्लाई चेन को अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाने पर भी फोकस रहेगा, ताकि वैश्विक चुनौतियों के बीच दोनों देशों की अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम बन सके.

रक्षा और रणनीतिक सहयोग भी बैठक का अहम विषय रहेगा. भारत और जापान लंबे समय से मुक्त और सुरक्षित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के पक्षधर रहे हैं. ऐसे में समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को मजबूत करने पर दोनों नेताओं के बीच विस्तार से चर्चा होगी.

आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूरे होने के उत्सव के रूप में 'स्वर प्रेरणा वीथिका' का अनावरण किया

पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने महान संगीतकारों के सम्मान में फोटो गैलरी का उद्घाटन किया

(जीएनएस)।

आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर और 2027 में भारत में रेडियो प्रसारण के 100 वर्ष पूरे होने की तैयारी के तहत, आकाशवाणी ने आज आकाशवाणी और भारत के महान संगीतकारों के बीच अटूट संबंधों को समर्पित एक फोटो गैलरी 'स्वर प्रेरणा वीथिका' का अनावरण किया। इसका उद्घाटन पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन के आकाशवाणी रंग भवन सभागार में किया।

लगभग नौ दशकों से, आकाशवाणी देश के प्रमुख लोक सेवा प्रसारक के रूप में काम कर रहा है। इसने देश भर के लाखों श्रोताओं तक महान कलाकारों की प्रस्तुतियां पहुंचाकर भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संजोया और बढ़ावा दिया है। इसी शानदार विरासत के सम्मान में 'स्वर प्रेरणा वीथिका' की शुरूआत की गई है। यह उन प्रख्यात कलाकारों को सम्मानित करती है जो आकाशवाणी से गहराई से जुड़े रहे और जिन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया। इस पहल का उद्देश्य भारतीय संगीत में उनके अमूल्य योगदान को संजोये रखना और साथ ही कलाकारों व संगीत प्रेमियों की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना है।

पहल के पहले चरण में, 20 प्रतिष्ठित संगीत दिग्गजों के चित्रों का अनावरण किया गया। इस गैलरी में भारत रत्न से सम्मानित विदुषी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी (कर्नाटक गायन), पं. रविशंकर (सितार), विदुषी लता मंगेशकर (पार्श्व गायन), उस्ताद बिस्मिल्लाह खान (शहनाई), पं. भीमसेन जोशी (हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन) और डॉ. भूपेन हजारिका

(लोक संगीत) के चित्र शामिल हैं। साथ ही पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया (बांसुरी), उस्ताद अमजद अली खान (सरोद) और उस्ताद अलाउद्दीन खान (सरोद), पं. बिरजू महाराज (कथक) और पद्म भूषण पुरस्कार विजेताओं उस्ताद हाफिज अली खान (सरोद), उस्ताद अहमद जान थिरकवा (तबला), पं. कृष्णराव शंकर पंडित (हिन्दुस्तानी गायन), विदुषी शन्नो खुराना (गायन), पं. देबू चौधरी (सितार), विदुषी शरण रानी बैकलीवाल (सरोद), उस्ताद साबरी खान (सारंगी), पं. राजन मिश्र एवं पं. साजन मिश्रा (हिंदुस्तानी गायन), उस्ताद असद अली खान (रुद्र वीणा) और उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान (हिंदुस्तानी गायन) के चित्र भी शामिल है।

इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव द्विवेदी ने कहा कि 'स्वर प्रेरणा वीथिका' का उद्घाटन आकाशवाणी की उन महान कलाकारों के प्रति आभार व्यक्त करने की कोशिशों का पहला चरण है, जिनके अमूल्य योगदान ने आकाशवाणी को देश के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों में से एक के रूप में स्थापित करने में मदद की। उन्होंने कहा कि बाद के चरणों में गैलरी में और भी मशहूर कलाकारों के चित्र शामिल किए जाएंगे तथा देश भर के आकाशवाणी केंद्रों पर खास स्थानीय संगीतकारों को समर्पित ऐसी ही गैलरी भी बनाई जाएंगी।

भारतीय संगीत के प्रति आकाशवाणी की दृढ़ प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस लोक प्रसारक ने अलग-अलग पीढ़ियों के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच देकर और श्रोताओं की विविध पसंद का ध्यान रखते हुए, संगीत की विभिन्न परंपराओं को लगातार बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के समर्पित डिजिटल चैनलझ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए 'रागम' और भक्ति संगीत के लिए 'आराधना'झ यूट्यूब, न्यूज ऑन एयर ऐप और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चौबीसों घंटे उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के कलाकारों ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को देश और दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है।

उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने इस अवसर को "घर वापसी" जैसा बताया। उन्होंने याद किया कि आकाशवाणी के साथ उनका संगीत का सफर बच्चों के कार्यक्रम से शुरू हुआ था। आकाशवाणी को कलाकारों की कई पीढ़ियों को संवारने वाला एक परिवार बताते हुए, उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि यह समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा आगे भी फलती-फूलती रहेगी और संस्थान को देश भर के श्रोताओं का प्यार और स्नेह मिलता रहेगा। इस कार्यक्रम को पंडित रूपक कुलकर्णी के मनमोहक बांसुरी वादन ने और समृद्ध किया। पंडित रूपक कुलकर्णी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सबसे खास शिष्यों में से एक हैं।

केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए परभणी स्थित वीएनएमकेवी में खाद्य एवं खाद्य प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित साझा इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया

श्री चिराग पासवान ने वीएनएमकेवी के खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में उन्नत साझा इनक्यूबेशन केंद्र का शुभारंभ किया, जिससे मूल्यवर्धन और किसान सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी

(जीएनएस)।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की वित्तीय सहायता से और वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परभनी तथा महाराष्ट्र सरकार के कृषि विभाग की राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के सहयोग से स्थापित एक उन्नत कॉमन इन्क्यूबेशन सेंटर (सीआईसी) का उद्घाटन 28 जून, 2026 को किया।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती दीक्षांत समारोह हॉल में उनके द्वारा एक विशेष संवाद एवं मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, ऊर्जा, महिला एवं बाल विकास, लोक निर्माण (सार्वजनिक उपक्रम) राज्य मंत्री और परभणी जिले की पालक मंत्री श्रीमती मेघना ताई बोरदिकर भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो. (डॉ.) इंद्र मणि ने की। विशिष्ट अतिथियों में राज्यसभा सदस्य श्री रामराव वाडकुटे, लोकसभा सदस्य श्री संजय जाधव, महाराष्ट्र सरकार के कृषि प्रसंस्करण योजना निदेशक श्री विनयकुमार अवाटे, कार्यवाहक जिला कलेक्टर एवं जिला परिषद प्रमुख श्रीमती नतिशा माथुर (आईएएस), पुलिस अधीक्षक श्री पंकज कुमावत (आईपीएस) और शिक्षा निदेशक डॉ. भगवान असेवार शामिल थे।

अपने उद्घाटन भाषण में केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों के उत्साह को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें इस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है और वे इसे समान

उत्साह और समर्पण के साथ निभा रहे हैं। विश्वविद्यालय में मौजूद लोगों के उत्साह को देखकर उन्हें श्रोताओं से सीधे संवाद करने की प्रेरणा मिली।

श्री चिराग पासवान ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि ही देश की आय का प्राथमिक स्रोत है। इसलिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। प्रारंभ में, भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया और आज देश उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ कई देशों को निर्यात भी करता है। हालांकि, अब कृषि उत्पादों में मूल्यवर्धन करके उन्हें उच्च मूल्य वाले उत्पादों में परिवर्तित करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि परंपरागत रूप से भारतीय परिवार दही, पापड़ और अचार जैसे उत्पादों को घर पर ही कुशलतापूर्वक संसाधित करते आए हैं, और इसी प्रकार आधुनिक कृषि उत्पादों का भी प्रसंस्करण किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कृषि आय बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण आवश्यक है और इसे अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

श्री चिराग पासवान ने बताया कि कई किसानों के पास छोटी जमीनें हैं लेकिन उनकी आर्थिक जरूरतें ज्यादा हैं, जिसके चलते अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं के कारण उन्हें अपनी उपज कम दामों पर बेचनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि किसानों की क्षमता बढ़ाना जरूरी है ताकि वे अपनी उपज का भंडारण, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन कर सकें, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि औद्योगिक क्षेत्र में अपार क्षमता है और युवाओं को रोजगार चाहने वालों के बजाय रोजगार देने वाले बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उत्पादन से लेकर विपणन तक सभी हितधारकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं लागू कर रहा है। खाद्य अपशिष्ट एक गंभीर समस्या बनी हुई है और ऐसे नुकसान को कम करने के लिए प्रसंस्करण सबसे प्रभावी समाधान है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विस्तार आवश्यक है और राज्य सरकारों का सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि महाराष्ट्र ने पीएमएफएमई योजना (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना) के तहत असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है और देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि भारतीय कृषि उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना और जैविक खेती को अपनाना आवश्यक है। गुणवत्तापूर्ण प्रसंस्कृत उत्पादों का विकास भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कार्यान्वित की जा रही "खेत बचाओ अभियान" जैसी पहलों से इस उद्देश्य को प्राप्त करने में काफी लाभ होगा।

छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने सलाह दी कि वे चाहे जो भी क्षेत्र चुनें, अपने उत्पादों की गुणवत्ता से कभी समझौता न करें। केवल गुणवत्तापूर्ण उत्पाद ही लंबे समय तक टिकते हैं और एक स्थायी पहचान बनाते हैं। कई सफल ब्रांड वर्षों की कड़ी मेहनत से बनते हैं, लेकिन अल्पकालिक लाभ के लिए गुणवत्ता से समझौता करना वर्षों की मेहनत को पल भर में बर्बाद कर सकता है। इसलिए, उन्होंने छात्रों से गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि "मेड इन इंडिया" लेबल वाले प्रत्येक उत्पाद को उत्कृष्टता के सभी मानकों को पूरा करना चाहिए और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। श्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण को दोहराया कि भारतीय किसानों में विश्व का खाद्य भंडार बनने की क्षमता है।

अंत में उन्होंने कहा कि वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ की स्थापना महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वसंतराव नाइक के दूरदर्शी विचारों पर आधारित है। विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और कृषि विस्तार में अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने विश्वविद्यालय, विभाग और राष्ट्र से इस विरासत को आगे बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाने की अपील की।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में डेंगू को लेकर तैयारियों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली में डेंगू की रोकथाम, निगरानी और अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की

डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए सक्रिय तैयारी, गहन निगरानी, अस्पतालों की मजबूत तैयारी और 'जन भागीदारी के माध्यम से जन चेतना' का आ'ान किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने भारत सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत करने और मौसमी वेक्टर जनित रोगों के लिए समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयासों के तहत आज दिल्ली में डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण की तैयारियों का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में महामारी विज्ञान की बदलती स्थिति की समीक्षा करने और स्वास्थ्य संस्थानों एवं नागरिक एजेंसियों की तैयारियों का मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

विचार-विमर्श में महामारी को लेकर स्थिति की व्यापक समीक्षा, नगर निकायों, अस्पतालों और राज्य सरकार की तैयारियों की समीक्षा और निगरानी प्रणालियों, नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल और वेक्टर नियंत्रण उपायों का आकलन शामिल था।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को देश भर में डेंगू की स्थिति और उससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई, जिसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया। दिल्ली में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें रोग निगरानी, वेक्टर प्रबंधन, मामलों का पता लगाने, नैदानिक प्रबंधन और जन जागरूकता को मजबूत करने के प्रमुख उपायों पर प्रकाश डाला गया।

बैठक में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रणनीति के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई, जिसे दिल्ली सहित पूरे देश में लागू किया जा रहा है। 'ऑक्टालॉग' के नाम से जानी जाने वाली यह रणनीति आठ स्तंभों - निगरानी, मामलों का प्रबंधन,

वेक्टर प्रबंधन, प्रकोप से निपटना, क्षमता निर्माण, व्यवहार परिवर्तन संचार, अंतर-क्षेत्रीय समन्वय और निगरानी एवं पर्यवेक्षण पर आधारित है। यह भी बताया गया कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय डेंगू नियंत्रण (एनएचएम) के तहत सलाह जारी करना, उच्च स्तरीय समीक्षा, मामलों के प्रबंधन पर प्रशिक्षण, मुफ्त निदान सुविधाओं का प्रावधान, सामुदायिक जागरूकता अभियान, अंतर-मंत्रालयी समन्वय और वित्तीय सहायता सहित कई कदम उठाए हैं।

सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि डेंगू के मामले वर्तमान में कम हैं और मृत्यु दर मात्र 0.11 प्रतिशत है। हालांकि, उन्होंने आने वाले महीनों में संभावित खतरे के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने विशेष रूप से आगामी महीनों के लिए तैयारी पर जोर दिया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगरपालिका निकाय किसी भी संभावित प्रकोप का पूर्वानुमान लगाने और उससे निपटने के लिए सक्रिय रूप से तैयार रहें और अपनी तत्परता का स्पष्ट प्रदर्शन करें। उन्होंने आक्रामक सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समुदाय में डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नवीन रणनीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जैसे कि स्कूलों, श्रमिक शिविरों और डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाना। उन्होंने "जन भागीदारी के माध्यम से जन चेतना" के संदेश को उजागर करते हुए राज्यों से वार्ड आयुक्तों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और आरडब्ल्यूए को जागरूकता और रोकथाम प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल करने का आ'ान किया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली में डेंगू से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने बुखार के बढ़ते मामलों वाले क्षेत्रों में वेक्टर नियंत्रण को तेज करने पर जोर दिया। हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए कीट जनित रोगों की निगरानी को मजबूत करने और सभी प्रभावित क्षेत्रों में बुखार की निगरानी को तेज करने पर भी बल दिया गया।

श्री नड्डा ने समर्पित वार्ड, पर्याप्त बिस्तर, रक्त घटक, निदान उपकरण, दवाएं और कीटनाशक उपलब्ध कराकर अस्पतालों की तत्परता सुनिश्चित करने और सेंटिनल सर्विलांस अस्पतालों (एसएसएचए) के साथ-साथ अन्य सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को सतर्क करने का आ'ान किया। तत्काल निवारक कार्रवाई के लिए त्वरित प्रतिक्रिया टीमों के साथ एक त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त, निजी अस्पतालों सहित सभी अस्पतालों से आईएचआईपी-वीबीडी पर मामलों की समय पर रिपोर्टिंग और प्रकोपों और प्रतिक्रियाओं पर नजर रखने के लिए दैनिक जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों का आयोजन अनिवार्य किया गया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रभावी स्वच्छता और मच्छर नियंत्रण अभियानों को सुनिश्चित करने के लिए नगर निकायों, रेलवे, छावनी बोर्ड, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य विभागों के बीच अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को मजबूत करने के महत्व पर भी बल दिया।

उन्होंने विशेष रूप से आज से शुरू होने वाले जुलाई के "डेंगू-विरोधी माह" के दौरान आईईसी गतिविधियों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने का आग्रह किया। इसके तहत मच्छरदानी और पूरी बाजू के कपड़े पहनने जैसे निवारक उपायों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आईईसी और जागरूकता अभियान चलाए जाएं और स्कूलों, आरडब्ल्यूए, बाजार संघों, सामुदायिक नेताओं, स्वयं सहायता समूहों और युवा क्लबों का सहयोग लिया जाए।

इस बैठक में दिल्ली में डेंगू से निपटने की तैयारियों का समग्र मूल्यांकन किया गया, रोकथाम, प्रकोप से निपटने और वेक्टर प्रबंधन के लिए तत्काल कार्रवाई बिंदुओं की पहचान की गई और मौजूदा मौसम के दौरान बढ़े हुए जोखिम को देखते हुए अस्पताल की तैयारियों और निगरानी को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई।